Universe Journal of Education & Humanities ISSN 2348-3067
Volume-5, No. II, Aug.-2018, pp.Hin.07-12

# भारत में भूमण्डलीय व्यवस्था

**डा0 नगेन्द्र पाल,**
असिस्टेंट प्रोफेसर राजनीति विज्ञान,
राजकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय काण्डा बागेश्वर उत्तराखण्ड भारत।

आजाद भारत के इतिहास में 15 अगस्त 1947 की तारीख का मतलब सभी को मालूम है, पर 24 जुलाई 1991 के महत्व का अहसास अभी बहुत कम लोगों को हो पाया है। 15 अगस्त एक आधुनिक राष्ट्र को साकार होने की शुरूआत थी। इस सिलसिले के केन्द्र में थी लोकतांत्रिक राजनीति। लेकिन उस साकार राष्ट्र को निराकार करने की तरफ पहला कदम 24 जुलाई को उठाया गया था। आजादी रात के 12 बजे मिली लेकिन उसके तकरीबन 44 साल बाद जो सुबह आयी उसने एक नयी उद्योग नीति की घोषणा की और उसी दिन दोपहर के बाद संसद में नया केन्द्रीय बजट पेश किया गया जिसमें एक ऐसे अर्थतन्त्र का आकार बनना शुरू हुआ जो राजनीति से नियन्त्रित होने की बजाय उसे नियंत्रित करने की इच्छा से लैस था। चार दशक से ज्यादा की अवधि में जिस राष्ट्रीय राजनीतिक–सामाजिक–संस्कृति की रचना हुई थी एक पल में जिसकी बागडोर ऐसे हाथों में चली गयी जो शुद्ध रूप से भारतीय हाथ नहीं थे यह भारत के ग्लोबलाइजेशन यानि भूमण्डलीकरण की शुरूआत थी।

**मुख्य शब्द**– भूमण्डलीकरण, रिमोट सेसिंग, ग्रामीण अर्थव्यवस्था

बीसवीं शताब्दी में विश्व ने प्रथम विश्व युद्ध, द्वितीय विश्व युद्ध और इन दोनों के बीच यूरोपीय देशों के अधीन अनेक उपनिवेशों में स्वतन्त्रता आन्दोलनों की लहर एवं उससे बाध्य होकर उन्हें स्वतन्त्र किया जाना, द्वितीय विश्व युद्ध के बाद सोवियत संघ और इसके नेतृत्व में पूर्वी यूरोपीय देशों में साम्यवाद के अधीन सर्वाधिकारवादी सरकारों की स्थापना, चीन और क्यूबा में साम्यवादी सरकार की स्थापना, पूंजीवाद और साम्यवाद के बीच चला शीत युद्ध अनेक अविश्वसनीय सी लगने वाली घटनायें देखी, लेकिन सर्वाधिक चौकाने वाली घटनायें बीसवीं शताब्दी के अन्तिम दशक में घटित हुई। ''ग्लासनोतस और पेरेस्त्रोइका'' नीतियों के तहत सोवियत संघ के विघटन के बाद 15 नये स्वतन्त्र देशों का उदय हुआ तो समूचे यूरोप ने साम्यवाद की अन्तिम सांस ली। संयुक्त राज्य अमेरिका के नेतृत्व में, विश्व बैंक, अन्तर्राष्ट्रीय मुद्राकोष तथा 5 जनवरी 1995 को गैट के स्थान पर अस्तित्व में आये डब्लू0टी0ओ0 ने आर्थिक क्षेत्रों में जिन नीतियों को अपनाने पर तृतीय विश्व के देशों पर दबाव डाला उसे एल0पी0जी0 की नीति कहा गया।

1970 के दशक से विश्वस्तर पर ग्रामीण अर्थव्यवस्था में सुधार के लगातार प्रयास हुए। वर्तमान में विकासशील देशों में ग्रामीण क्षेत्रों से निर्धनता उन्मूलन और असमानता जैसी समस्याओं के मूल्यांकन करने में उद्योगतन्त्रीय मार्ग समाप्त हो चुके हैं और अब ग्रामीण विकास को योजनाबद्ध तरीके से बढ़ावा देने की विचारशैली का विकास हुआ है जो अपने बहुआयामी दृष्टिकोण से कृषि और औद्योगिक विकास बढ़ाने में बुनियादी प्रयास के साथ–साथ शिक्षा स्वास्थ्य सेवाएं और रोजगार प्रदान करने के अतिरिक्त ग्रामीण क्षेत्रों में निर्धनता पर विशिष्ट ध्यान केन्द्रित करती है। ग्रामीण विकास का अर्थ लोगों को होने वाले अधिकाधिक परिवर्तन से लगाया जाता है। ग्रामीण लोगों के लिए आर्थिक विकास की सम्भावनाएं उसी स्थिति में हो सकती है जब ग्रामीण विकास प्रक्रिया में जनता की अधिकाधिक सहभागिता सुनिश्चित की जाये, योजना का विकेन्द्रीकरण किया जाये, भूमि सुधारों को उत्तम तरीके से क्रियान्वित किया जाये और सामाजिक विकास के लिए स्वास्थ्य, शिक्षा, पेयजल, ऊर्जा आपूर्ति, स्वच्छ आवास आदि में सुधार और ग्रामजनों की मनोवृत्ति में परिवर्तन भी समान रूप से आवश्यक है।

ग्रामीण विकास मंत्रालय हमारे गांव से गरीबी और भूख की स्थिति को बदलने तथा ग्रामीण भारत का समस्त विकास करने के लिए कृतसंकल्प है। इस प्रतिबद्धता के अनुरूप पिछले कुछ वर्षों में ग्रामीण विकास को सर्वोच्च प्राथमिकता दी गयी है। नये कार्यक्रमों की शुरूआत और पहले के कार्यक्रमों को पुनः पहले की तरह तैयार किये जाये जिससे वे और अधिक प्रभावशाली बन सके।

डॉ0 सी0 रंगराजन के अनुसार ''भूमण्डलीकरण से समाज में सभी को लाभ होता है परन्तु दुभाग्यवश यह विभिन्न वस्तुओं और विभिन्न व्यक्तियों से



Scanned by CamScanner

सम्बन्धित होता है। भूमण्डलीकरण पर जोर देते हुए वे कहते हैं कि इसके द्वारा संसार में प्रत्येक राष्ट्र आर्थिक रूप और समाज, सूचना, विचार, तकनीक, वस्तुएं, व्यापार सेवाऐं, वित्त और व्यक्ति आपस में जुड़ते हैं। इस प्रकार भूमण्डलीकरण मानवीय जीवन के प्रत्येक पहलू से जुड़ता है।''

भारत में नई आर्थिक नीति के अन्तर्गत भूमण्डलीकरण, उदारीकरण और निजीकरण तीन महत्वपूर्ण अंग है यदि इनमें भूमण्डलीकरण को ले तो यह भारत की अर्थव्यवस्था को दुनिया की अर्थव्यवस्था से मिलाता है। यद्यपि आयात के शुल्कों में भी कमी करके व निर्यात शुल्कों में कमी करके, विदेश तकनीकी तथा विदेशी निवेश को बढ़ाया जा सकता है। दूसरी तरफ उदारीकरण के अन्तर्गत नौकरशाही तथा निजी उद्यम को नियन्त्रित किया जा सकता है, निजीकरण एक ऐसी प्रक्रिया है जिसके तहत सरकारी उद्यमों को निजी उद्योगों के अधिकार में लाया जा सके जिससे भारतीय अर्थव्यवस्था में सरकारी उद्यमों का विराष्ट्रीयकरण हो जाता है। इन सभी प्रक्रियाओं के तहत भारतीय अर्थव्यवस्था से राष्ट्रीय आय, पूर्ण रोजगार, स्वतः उद्योग तथा विभिन्न असमानताऐं व गरीबी दूर होती हैं। भूमण्डलीकरण बहुत दूर का अनुभव नहीं है वह भारतीय लोगों से पूर्णतः गायब नहीं हुआ है। यदि विदेशी मुद्रा नयी तकनीक लाती है तो यह रोजगार को बढ़ायेगी या अधिक रोजगार को घटायेगी।

भूमण्डलीकरण के इस दौर में भारत ने अपनी भागेदारी की घोषणा 1991 में की जब विदेशी मुद्रा संकट के कारण कांग्रेस की नरसिंहराव सरकार ने अन्तर्राष्ट्रीय मुद्राकोष से कर्ज लिया। अन्तर्राष्ट्रीय वित्त पूंजी द्वारा निवेशित ढांचागत समायोजन कार्यक्रम अपनाने का निर्णय किया गया, जिसका मतलब था लोकहितकारी राज्य की संरचना को बदलकर आयात प्रतिस्थापन की जगह निर्यातान्मुख विकासनीति पर आधारित बाजारोन्मुख नीतियां अपनाना, बड़े पैमाने पर निजीकरण का कार्यक्रम चलाना, विदेशी पूंजी को प्रोत्साहित करने वाली नीतियों को अपनाना तथा लाइसेन्स–परमिट राज खत्म करके वाणिज्य और उद्योग नीति में भारी बदलाव लाना।

गुरूचरण दास ने अपनी पुस्तक 'इण्डिया अनबाउंड' में भूमण्डलीकरण की शुरूआत बड़े दिलचस्प अंदाज में की है। दास के अनुसार ''21 जून 1991 को राव सरकार ने शपथ ली और अगले दिन राष्ट्र को बताया कि आर्थिक संकट की तलवार सिर पर झूल रही है। उनके वित्तमंत्री मनमोहन सिंह ने पहला कदम यह उठाया कि रिजर्व बैंक के गवर्नर वेंकिटरमन से विदेशी मुद्रा कोष के बारे में रिपोर्ट मांगी जिससे पता चला कि भारत के पास दो हफ्ते के आयात का बिल चुकाने लायक क्षमता रह गयी है और उनके पास मुद्रा कोष से कर्ज लेने के सिवाय कोई चारा नहीं रह गया है।''

इसी कारण जुलाई में दो चरणों में रूपये का बीस फीसदी अवमूल्यन किया गया और इसी आधार पर डॉ0 मनमोहन सिंह और वाणिज्य मंत्री पी0 चिदम्बरम ने नयी वाणिज्य नीति बनायी। तदोपरान्त राव ने उद्योग नीति घोषित की।

भूमण्डलीकरण के इस वर्तमान दौर में संचार की इस नई क्रान्ति से संसार एक ''ग्लोबल विलेज'' बनने की बजाय एक ''ग्लोबल सुपर मार्किट'' बन रहा है जिसमें प्रत्येक व्यक्ति अपनी जरूरत को पूरी कर सकता है और संचार क्रान्ति के द्वारा उन्हीं वस्तुओं को प्राप्त करने का लाभ होगा जो सूचना से सम्बन्धित हैं जैसे अखबार, किताब, समाचार, संगीत। ये दुनिया के किसी कोने पर चन्द मिनटों में पहुंच सकती है।

भारत सरकार ने 1991 के मध्य आर्थिक सुधार किये। जिसके आधार पर अंकित मेहता और सांची त्रिवेदी ने कहा कि ''भारत में स्थायित्व कार्यक्रम मुद्रा स्फीति को उदार स्तर पर घटाने में सफल है और आई0एम0एफ0 / विश्व बैंक के भारतीय आयात पर बिना उसके लाभदायक ऋण सर्विस चार्ट को हानि पहुंचाये, प्रतिबन्ध लगाने में सहायता की है और इसलिए स्थायित्व की नीति में संरचनात्मक बदलाव आवश्यक है और एक सरकार के हाथ से शासन दूसरी सरकार के हाथ में जाना चाहिए लेकिन अभी भी भारत को आर्थिक क्षेत्र की आधुनिक अर्थव्यवस्था में मिलाने के लिए एक लम्बा सफर तय करना पड़ेगा।

अरविन्द विरमानी ने अपनी लेख ''इण्डिया क्राइसिस'' में आर्थिक सुधारों और अर्थव्यवस्था की वृद्धि के बारे में उपसंहार दिया है कि अर्थव्यवस्था के प्रदर्शन पर विश्लेषण करने पर यह सिद्ध हो गया है कि जहां पर सुधार अत्यधिक विस्तृत होते हैं वहां तीव्र गति से वृद्धि होती है और जहां सुधार कम होते हैं वहां अवनति होती है।

आधुनिक दुनिया में भूमण्डलीकरण और उदारीकरण की प्रक्रियायें भारतीय व्यवस्था पर अपना गहरा प्रभाव डाल रही है और 1931 से नियंत्रित एवं आंतरिक दृष्टि रखने वाली अर्थव्यवस्था बाह्य दृष्टि वाली हो रही है तथा राज्य के अधिकांश उद्यम का स्थान निजी उद्यम ले रहे हैं। भारत की मिश्रित अर्थव्यवस्था में निजी तथा सार्वजनिक क्षेत्र दोनों भूमिका निभा रहे हैं तथा सार्वजनिक क्षेत्र बहुत क्षेत्रों में निजी उद्योगों को नियन्त्रित करते हैं, जैसे लाइसेन्स और परमिट



Scanned by CamScanner

देना। भूमण्डलीकरण ने व्यापार और उद्योग से नियन्त्रण को समाप्त करने पर ध्यान दिया है और कर व सीमा शुल्क को भी घटाया है इन सभी कदमों ने घरेलू तथा विदेशी दोनों निवेशों के लिए उपयुक्त वातावरण का निर्माण किया है इस प्रकार उदारीकरण के कारण अनुदार अर्थव्यवस्था का उदार एवं निर्यातोन्मुखी अर्थव्यवस्था में रूपांतरण हुआ। भूमण्डलीकरण के दूसरे चरण में उदारीकरण और निजीकरण की प्रक्रिया तेज हुई है। और इस चरण में दो मुख्यः बातों पर अधिक बल दिया गया, प्रत्यक्ष विदेशी निवेश को अधिक बढ़ावा दिया जा रहा है तथा सार्वजनिक क्षेत्र के आकार को छोटा किया जा रहा है। भारत एक बड़ा बाजार है। सभी प्रकार के परिणात्मक अवरोधों को 1 अप्रैल 2001 को समाप्त कर दिया। अब भारतीय बाजार विदेशी सामानों के लिए खुला हुआ है तथा सार्वजनिक क्षेत्रों के उद्यमों में न केवल विनिवेश प्रारम्भ हो गया है बल्कि कई निगम निजी उद्यमियों को बेच भी दिये गये है हाल ही में सूचना तकनीक के क्षेत्र में भारतीय व्यवसायियों की गुणवत्ता सिद्ध हो चुकी है, जिसकी मांग विश्व के विकसित देशों में काफी है। यह अपेक्षा की जा रही है कि आने वाले वर्षो में सूचना तकनीक से सम्बन्धित सेवाओं से भारतीय अर्थव्यवस्था को नया आयाम मिलेगा।

भूमण्डलीकरण से किसी भी देश के प्रतिस्पर्धात्मक वातावरण में परिवर्तन आता है भारत भी इसका अपवाद नहीं है हर प्रतिस्पर्धात्मक महौल में परिवर्तन के कारण व्यापार नीति में परिवर्तन लाना पड़ता है तथा भूमण्डलीकरण के लिए पूरी अर्थव्यवस्था को ज्ञान अर्थव्यवस्था में परिवर्तन करना आवश्यक है भारत ने इसके लिए लगभग 250 विश्वविद्यालय (900 से अधिक कालिज) हैं। जहां डिग्री/डिप्लोमा स्तर की कम्प्यूटर शिक्षा भी दी जाती है। इसमें छात्रों की संख्या निरन्तर बढ़ रही है इसी प्रकार भारतीय दूरसंचार क्षेत्र का कारोबार 2002 में अनुमानतः 9 अरब अमेरिकी डॉलर तक पहुँच चुका था। सूचनाओं के अनुसार इसका बाजार 1996–97 से साल दर साल 20 प्रतिशत से अधिक की दर से बढ़ता जा रहा है और इससे सूचना टैक्नोलोजी निर्यात क्षेत्र में नये बाजार खुल रहे हैं और इसमें अनुसंधान विकास तथा साफ्टवेयर उत्पादों का बहुत महत्व है और भारत में बहुत सी बहुराष्ट्रीय कम्पनियां अनुसंधान और विकास सुविधाओं का इस्तेमाल कर रही है।

सूचना प्रौद्योगिकी में भारतीय विशेषज्ञों की कुशलता का लाभ दुनिया के विकसित देश भी उठा रहे हैं। भूमण्डलीकरण की ताजा हवा गांवों में सूचना प्रौद्योगिकी के रूप में दस्तक दे चुकी है तथा सूचना प्रौद्योगिकी से दुनिया में ई–कॉमर्स, दूरस्थ शिक्षा, टेली मेडिसिन एवं ई–गवर्नेस आदि नयी सेवाऐं ली जा रही हैं। भारत में केन्द्र सरकार ने कम्प्यूटर निर्माता कम्पनियों से ऐसे कम्प्यूटर बनाने को कहा है जिस पर भारतीय भाषाओं में काम करना सम्भव हो। आज भारत में हिन्दी और अन्य भारतीय भाषाओं के अनेक साफ्टवेयर मौजूद है। भारत की आई0टी0सी0 कम्पनी को ई0 चोपाल के लिए प्रतिष्ठित डेवलपमेन्ट गेटवे अवार्ड से नवाजा गया है। आज 31000 गाँवों के 35 लाख से अधिक किसान ई–चौपाल की पहुँच तक है इसके द्वारा किसानों को अपनी फसलों के बारे में विस्तृत जानकारी, खेती के उन्नत तरीके, सम्भावित मौसम की जानकारी स्थानीय भाषा के कम्प्यूटर से प्राप्त कर सकते हैं। हैदराबाद स्थित नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ एग्रीकल्चरल एक्सटेंशन मैनेजमेंट ने साइबर एक्सटेंशन नाम से एक महत्वाकांक्षी कार्यक्रम शुरू किया है। जिला स्तरीय वेबसाइटे तैयार कर इंटरनेट पर उपलब्ध करायी जा रही हैं। ब्लॉक, मण्डल और गांवों के स्तर पर इनफार्मेशन कियोस्क स्थापित किये जा रहे हैं। सहकारी समितियों के आय व्यय का लेखा जोखा रखने के लिए इस संस्था ने एक सरल एकाउंटिंग पैकेज भी तैयार किया है और अब गांवों में 50000 रूपये की कम लागत में एटीएम मशीन बनाने पर काम चल रहा है तथा गांवों में कम मूल्यों की बैटरी चालित कम्प्यूटर जिसे सिम्प्यूटर का नाम दिया गया है, विकसित किया गया है।

सन् 1991 से शुरू हुए भूमण्डलीकरण और आर्थिक उदारीकरण के दौर ने देश की आर्थिक वृद्धि दर को बढ़ाया है परन्तु समग्र सन्तुलित विकास नहीं हो सका है। आज यहाँ बाजार में अधिक पूँजी होने के कारण एक और ऋण लेने की सहज उपलब्धता है वही देश की अर्थव्यवस्था रीढ़ कहे जाने वाले अन्नदाता किसान लगातार आत्महत्या कर रहे हैं। तमाम प्रयासों के बावजूद 65 प्रतिशत कृषि अभी भी मानसून पर आश्रित है। यद्यपि भारतीय कृषि में ज्ञान विज्ञान की सहायता से किसानों को दूसरों की रिमोट सेसिंग तकनीक वरदान साबित हो सकती है। इस तकनीक से सूखाग्रस्त इलाके में कहां खुदाई करने पर पानी निकलेगा इसका पता चलता है। रोजगार की तलाश में ग्रामीण युवा शहरों की ओर भागता है और अधिक पैसा कमाने के चक्कर में आपराधिक कृत्य कर बैठता है। इस समस्या को दूर करने के लिए कृषि आधारित रोजगार व उद्योग विकसित करने होंगे। इस दिशा में मछली पालन और शहद उत्पादन करना होगा जिससे ग्रामीणों को दोहरा लाभ होगा। इसी तरह बकरी पालन, फल उद्योग, रस्सी उद्योग, कागज व कपड़ा, सिलाई, बुनाई व कढ़ाई, प्रिंटिंग, कम्पोजिंग, साबुन



Scanned by CamScanner

ISSN 2348-3067

बनाना, चाक बनाना, इलेक्ट्रानिक उपकरण, मशीनों के पुर्जे, कम्प्यूटर दुर्लभ जडी बूटी, पवन चक्की व सोलन प्लांट जैसे क्षेत्रों में और अधिक सम्भावनाएं हैं। शहरी औद्योगीकरण व प्रदूषण से शहरी लोग गांवों की तरफ शुद्ध वातावरण में जाना चाहते हैं। निश्चित रूप से "लौटे प्रकृति की ओर" यह भविष्य का नारा होगा। इसलिए ग्रामीण पर्यटन उद्योग में आपार सम्भावनाऐ हैं और दसवीं पंचवर्षीय योजना में इसका प्रावधान है। आंकड़ों के अनुसार इण्डिया विजन 2020 तक सकल घरेलू उत्पाद में कृषि की भागेदारी घटकर जहां 22 प्रतिशत से 6 प्रतिशत रह जायेगी वही उद्योगों की भागेदारी 26 प्रतिशत से बढ़कर 34 प्रतिशत तक होने का अनुमान है और भारत ने आपरेशन फ्लड और श्वेत क्रान्ति के चलते दुग्ध उत्पादन में विश्व में प्रथम स्थान पाप्त कर लिया है। ग्रामीण क्षेत्रों में शहरों की सुविधाओं की उपलब्धता प्रदान करने के लिए पूरा (PURA) नामक महत्वाकांक्षी कार्यक्रम की घोषणा 15 अगस्त 2003 को प्रधानमंत्री द्वारा लालकिले से की गयी थी जिसमें चार प्रकार की सुविधाओं को गांव से जोड़ने की बात की गयी है इसमें सड़क, परिवहन, विद्युत, इलैक्ट्रानिक ज्ञान व बाजार को गांव से जोड़ा जायेगा। भारत में रेशम उत्पादन की भी अपार सम्भावनाऐं हैं इसी प्रकार बायोडिजल की भी नये उद्योग के रूप में विकसित होने की संभावनाऐं जगी हैं। इसके अतिरिक्त अनाज व दाल शोधन, दियासलाई व अगरबत्ती, गुड़ व खाण्डसारी, साबुन, बढ़ईगिरी, लोहारगिरी, बेत का सामान, चाय व कॉफी के बागान, औषधि पौधों का उत्पादन, घरेलू वस्त्रों का निर्माण, कत्था, मक्का, व रोगी का प्रशोधन, रबर वस्तुओं का निर्माण, अनुसूचित क्षेत्रों में, अनुसूचित जनजाति क्षेत्रों में वन उत्पादों आदि अनेक क्षेत्रों में रोजगार की सम्भावनाओं के द्वार खुलते हैं।

भूमण्डलीकरण और आर्थिक उदारवाद की लहर में तेजी आने के फलस्वरूप देश के आर्थिक सामाजिक विकास के तौर तरीकों में भी बदलाव आया है। अर्थशास्त्रियों और समाजशास्त्रियों का एक वर्ग यह भी मानता है कि नई नीतियों के चलते समाज के उपेक्षित और हाशिये पर पड़े समुदायों के उत्थान पर पहले से कम ध्यान दिया जा रहा है। निजी क्षेत्र की बढ़ती भूमिका को देखते हुए यह धारणा बलवती हो रही है कि सरकारी तन्त्र के अन्तर्गत ग्रामीण क्षेत्रों के विकास की दिशा में जो प्रयास हो रहे थे, उनकी गति अब धीमी होने लगी है। गांवों में बुनियादी सेवाएं-शिक्षा, स्वास्थ्य, बिजली, सड़क, कृषि की उपेक्षा के साथ-साथ सरकारी क्षेत्रों के उद्योगों में हिस्सेदारी कम होने से रोजगार की स्थिति प्रभावित हो रही है। किन्तु दूसरी ओर यह दावा किया जा रहा है कि हवाई अड्डों, होटलों, बड़े-बड़े तकनीकी शिक्षा संस्थानों के निजी हाथों में चले जाने से सरकार अब बुनियादी सेवाओं, खासकर ग्रामीण क्षेत्रों के विकास के लिए अधिक धन खर्च करेगी।

भूमण्डलीकरण का लगभग तीन दशक का समय होने जा रहा है और इसका प्रभाव पूंजीवादी देश या समाजवादी देश कोई भी हो, स्पष्ट दिखाई देता है। इस नई पूंजीवादी अर्थव्यवस्था में हमें आर्थिक साम्राज्यवाद और उपनिवेशवाद की लहर दिखायी देती है। बाजार आधारित उपभोक्तावादी आर्थिक नीति के साथ भारत जैसे विकासशील राष्ट्र की समस्याऐं जटिल हैं साधन सीमित हैं, लेकिन साध्य बदलते जा रहे हैं। कल्पना की गयी थी कि विश्वव्यापी बाजार और तीव्र निर्यात संवर्धन से, जहां विकासशील राष्ट्र भी उन्मुक्त भाव से बाजार व्यवस्था का लाभ उठा सकते हैं लेकिन उपलब्धि निराशाजनक रही है। इससे न केवल विकसित और विकासशील देशों का अन्तर बढ़ता जा रहा है बल्कि देश के अन्दर भी अमीर और गरीब की खाई चौड़ी होती जा रही है। इसके फलस्वरूप शहरी और देहाती क्षेत्रों की दूरी भी व्यापक होती जा रही है।

इक्कीसवीं सदी में भारत के एक वैश्विक शक्ति के रूप में उभरने के अवसर जितने प्रबल हैं, उतने पहले कभी नहीं रहे। जब हम पीछे की ओर देखते हैं तो विश्वास करना कठिन होता है कि ज्यादा वक्त नहीं बीता, जब भारत धीमी गति से आगे बढ़ रहा गरीब विकासशील देश था, जो एक के बाद दूसरे संकट में उलझता जा रहा था। अपने सतत घाटे को पूरा करने के लिए यह बहारी सहायता पर आश्रित था। अपने भुगतान की समस्या पर नकेल कसने के लिए यह अन्तर्राष्ट्रीय मुद्राकोष से बराबर ऋण लिया करता था। वित्तीय और स्थायी संसाधनों की मांग कम करने के लिए नियन्त्रण और राशनिंग का प्रचलन था। लगातार बढ़ती जा रही विशाल जनसंख्या वाले इसी भारत को अब (संयुक्त राज्य अमेरिका और चीन के बाद) विश्व की सर्वाधिक महत्वपूर्ण अर्थव्यवस्थाओं में प्रस्तुत किया जा रहा है, जिसे अन्य देशों में लोकतंत्र के एक रोल मॉडल के रूप में देखा जा रहा है। जो कारक भारत के तीव्र परिवर्तन की व्याख्या करते हैं, उनमें शामिल है, उद्यमिता की ऊर्जा का प्रकट होना और प्रौद्योगिकी में आयी क्रान्ति के परिणामस्वरूप राष्ट्रों के तुलनात्मक लाभ की वैश्विक पद्धति में परिवर्तन।

वर्तमान समय में प्रजातान्त्रिक देशों में औद्योगिक तकनीकी क्रान्ति से अत्यधिक परिवर्तन आये हैं और परिवर्तन एक चक्र की भांति है, जो समय की गति के



Scanned by CamScanner

अनुसार घूमता रहता है। किसी भी बड़े देश में औद्योगिक तकनीकी क्रान्ति के कारण उसके मानव जीवन पर भी प्रभाव पड़ता है। इससे मानव का सामाजिक, आर्थिक और सांस्कृतिक तथा राजनीतिक जीवन भी अछूता नहीं रहता है। इन परिवर्तित होती स्थितियों का ग्रामीणों के विकास पर क्या प्रभाव पड़ रहा है। इसका वैज्ञानिक दृष्टि से अध्ययन करने का प्रयास किया गया है। वैश्वीकरण के साथ भारतीय कृषि का रिश्ता अभी नकारात्मक ही रहा है। केवल संचार के साधनों, सिंचाई के साधनों पर ही निजीकरण का प्रभाव स्पष्ट रूप से दिखायी दे रहा है। किसान भूमण्डलीकरण के दुष्परिणाम तो झेल रहे हैं पर उसके सकारात्मक परिणामों से वंचित हैं और विचार का प्रश्न यह है कि भूमण्डलीकरण का लाभ सभी क्षेत्रों को मिल रहा है पर कृषि क्षेत्र इससे अछूता क्यों है?

बाजार में यह एक विशद स्थिति है कि उपभोक्ता कार, रेस्तरा के बिल की कीमत बढ़ोत्तरी पर विवाद नहीं करता और यदि आलू, प्याज, गेहूँ के भावों में थोड़ी सी वृद्धि कर दी जाये तो उपभोक्ता उस पर बहुत हल्ला करते हैं। भारत से इनका निर्यात होता है तो घरेलू बाजार में इनकी कीमतें बढ़ जाती हैं, तो इसके निर्यात पर प्रतिबन्ध लगाने के लिए शोर मचने लगता है और उनके आयात की बाते होने लगती हैं व किसान को उनकी फसल की अच्छी कीमत नहीं मिल पाती हैं और यदि किसान गलती से प्याज और आलू की फसल मांग के हिसाब से ज्यादा पैदा कर लें तो फिर उन्हें अपने आलू, प्याज को लगभग मुफ्त में देने पड़ते हैं तब किसान के लिए कोई भी कुछ नहीं करता।

भारतीय किसान तब तक भूमण्डलीकरण का लाभ नहीं ले सकता जब तक उसे विदेशी बाजार में अपनी वस्तुए निर्यात करने में पूर्ण स्वतन्त्रता न मिल जाये। इसी कारण वह अपना घाटा स्वयं झेलता है। फिर भी इस बात पर विचार किया जाता है कि कृषि की विकास दर कम हो रही है सकल घरेलू उत्पाद में इसका योगदान लगातार गिरता जा रहा है। किसानों को यह बात समझ लेनी चाहिए कि सरकार के भरोसे पर बैठकर कुछ नहीं हो सकता उन्हें अपने रास्ते स्वयं तलाशकर अपने कृषि कार्य को भूमण्डलीकरण और बाजार से जोड़ने की कोशिश करनी चाहिए। रिटेल के क्षेत्र में तमाम कम्पनियां आ चुकी हैं। ये कम्पनियां किसानों को गेहू का मूल्य 16–17 रूपये किलो देती हैं जबकि अपने ब्राण्डेड आटे के रूप में करीब 25–30 रूपये किलो लेते है। आलू को चिप्स में बदलकर कई गुना मुनाफा कमाया जा रहा है जबकि किसान को आलू की सही कीमत नहीं मिल पाती हैं। बेहतर है कि कॉरपोरेट सेक्टर और किसानों के बीच बेहतर सम्बन्ध बने।

रिटेल क्षेत्र में भी स्थितियां तेजी से बदल रही हैं। पेप्सी के अलावा आई0टी0सी0, हिन्दुस्तान लीवर, टाटा, डी0सी0एम0, मैकडोनाल्ड के अलावा रिटेल के बड़े खिलाड़ी रिलायन्स का कारोबार फैलने के बाद कंपनियों का किसानों के दरवाजे पर जाने का सिलसिला बढ़ेगा और इसके लिए छोटे किसान भी कोऑपरेटिव बनाकर, सामूहिक गठजोड़ करके नई स्थितियों का लाभ ले सकते हैं। सरकार उनका अगर भला करती तो अब तक कर चुकी होती। इसलिए किसानों को नई स्थितियों में बाजार के लाभ स्वयं स्वयं उठाने चाहिए। इस प्रक्रिया का दुष्परिणाम देश के गरीब तबके के लिए गेहूँ–आटे की महंगी उपलब्धता की शक्ल में सामने आ सकता है इसके लिए जरूरी होगा कि सार्वजनिक वितरण प्रणाली को मजबूत बनाया जाये।

आधुनिक औद्योगिक व्यवस्था से किसानों के हित की बलि चढ़ायी जा रही है। चाहे नर्मदा जैसे बड़े बांधों से हो, राष्ट्रीय राजमार्गो के लिए भूमि अधिग्रहण से हो, औद्योगिक नगर बसाने के लिए हो या महानगरों या अभयारण्यों का प्रसार हो, सभी में किसानों का विस्थापन होता है। एक तरह से वर्तमान सभ्यता में विस्थापन किसानों की नियति बन गयी है। जो लोग कृषि को उद्योगों का दर्जा देने की वकालत करते हैं। वे या तो इसके निहितार्थ से अनभिज्ञ हैं या जानबूझकर बड़े उद्योगों और बड़े औद्योगिक कार्यों के विकास के लिए छोटे किसानों का अस्तित्व मिटाने का वातावरण बना रहे हैं। कृषि भूमि को हदबंदी कानून से मुक्त करने और कृषि में देशी और विदेशी पूंजी निवेश के लिए दरवाजा खोलने की पहल को इसी पृष्ठभूमि में देखा जाना चाहिए। एक बार यह शुरू हुआ तो धीरे–धीरे विपन्न होते छोटे किसान अपनी जमीन बड़े पूंजीपतियों के हाथ बेच देंगे और फिर आजीविका की तलाश में भटकेंगे।

हकीकत यह है कि छोटे किसान संरक्षित बाजार के भीतर ही अस्तित्व में रह सकते हैं। जहां विशाल उत्पादकों की प्रतिस्पर्धा से उन्हें लागत से कम भाव पर अपना उत्पाद बेचने की मजबूरी न हो। इसलिए छोटे किसानों के अस्तित्व यानी इस देश की दो तिहाई आबादी के अस्तित्व की रक्षा देश की वैश्विक बाजार की स्पर्धा से बचाने से ही सम्भव है लेकिन यह तो नहीं हो सकता कि हम खेती को स्पर्धा से मुक्त रखे और उद्योगों को वैश्विक व्यवस्था से जोड़े। इसलिए हमें कृषि और उद्योग दोनों में निवेश को समस्तर बनाना होगा। यानी छोटी तकनीक अपनानी होगी। यह हमारी अर्थव्यवस्था और जीवन के



Scanned by CamScanner

प्रतिमानों को एक नयी दिशा देने की माँग करती है। देश के बहुसंख्य लोगों की रक्षा के लिए हमें इस चुनौती को स्वीकार करना होगा।

## सन्दर्भ ग्रन्थ सूची


1. श्रीवास्तव आशीष ''भूमण्डलीकरण लाभ और हानि'' प्रतियोगिता दर्पण, सितम्बर 2004
2. नाइडू, वाई गुरूप्पा ''भूमण्डलीकरण का भारतीय समाज पर प्रभाव'' दि इण्डियन जनरल ऑफ पॉलिटिकल साइंस वोल्यूम LXVII नं0 1 जनवरी–मार्च 2006
3. सिन्हा, सच्चिदानन्दः भूमण्डलीकरण की चुनौतियाँ, सूचना और संचार, वाणी प्रकाशन, नई दिल्ली, 2003
4. कृत पारिख ''इण्डियाल इकानॉमीः प्रोइजड फोर टेक ऑफ'' इन पॉलिटिकल एण्ड इकॉनामिक, वीकली, मई 17–24, 1997
5. चौधरी सुजीत कुमार, ''भूमण्डलीकरण : नियन्त्रणवाद को चुनौती देती एक व्यवस्था'', सिविल सर्विसेज क्रॉनिकल, मार्च 2006
6. भारद्वाज रंगनाथ ''भूमण्डलीय अर्थव्यवस्था में ज्ञान'' योजना, फरवरी 2006
7. खेतान प्रभा ''बाजार के बीच : बाजार के खिलाफ, भूमण्डलीकरण और स्त्री के प्रश्न'' वाली प्रकाशन, नई दिल्ली, 2007
8. दुबे अभय कुमार 'भारत का भूमण्डलीकरण' वाणी प्रकाशन, नई दिल्ली, 2006
9. पटेल दशमन्त दास ''भारतीय अर्थव्यवस्था में भूमण्डलीकरण का दौर और ग्रामीण विकास'' कुरूक्षेत्र, जनवरी 2006
10. बेहरा, एम0सी0 ''ग्लोबलाइजिंग रूरल डवलपमेन्ट'' सेंग पब्लिकेशन, नई दिल्ली, 2006
11. अख्तर फरीदा ''भूमण्डलीकरण के युग में ग्रामीण विकास'' सेंग पब्लिकेशन, नई दिल्ली, 2005
12. सिंह कटार ''रूरल डवलपमेंट प्रिंपिपल्स पोलिसिज एण्ड मैनेजमेन्ट'', सेंग पब्लिकेशन, नई दिल्ली, 2006
13. शर्मा, डॉ0 के0के0 ''वैश्वीकरण एवं मानवाधिकार'' प्रतियागिता दर्पण, अगरत्त 2006
14. पुराणिक आलोक ''किसानों को मिले बाजार का लाभ'' अमर उजाला मेरठ, 29 नवम्बर 2006
15. सिंह तीर विजय ''आखिर कौन हो रहा है मॉल से मालामाल''? अमर उजाला मेरठ, जुलाई 2007
16. राव, सी0एच0 हनुमन्त ''आर्थिक उदारीकरण और कृषि योजना'' 15 अगरत्त, योजना, 2006
17. पाण्डे मृणाल ''ग्लोब गांव में गंवार और नस्ली छुआछूत'' हिन्दुस्तान, 11 फरवरी 2017
18. भाम्बरी सी0पी0 ''पोलिटिकल इकनॉकी ऑव दि इण्डियन स्टेटः 1991–1996'' इन शर्मा, आर0आर0 एण्ड लिवाईइमेयर
19. दत्त, शुभ्रकमल ''इण्डिया पर दयनीय भारत का ग्रहण'' अमर उजाला, 28 सितम्बर 2007
20. घोष, अरविन्द : ''ग्रामीण अर्थव्यवस्था में नई जान फूकने के प्रयास'' योजना, अगरत्त 2016
21. खण्डेल, मानचन्द्र–वैश्वीकरण और भारतीय व्यवस्था, आविष्कार पब्लिसर्श डिस्टीब्यूटर्स, जयपुर, पृ0 107, 2007
22. मिश्र, गिरीश, पाण्डे ब्रजकुमार–भूमण्डलीकरण मिथक या यथार्थ, अमिधा प्रकाशन, मुजफ्फरपुर, पृ0 35, 2005




Scanned by CamScanner